Dainik Jagran 24.03.2023

साइबर अपराध से निपटने को एक साथ काम करेगी राज्यों की पुलिस

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र योजना के तहत की गई पहल

- गृह मंत्रालय की ओर से गठित किया गया है संयुक्त समन्वय दल
- दिल्ली पुलिस को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: देश में बढ़ते साइबर अपराध के मामलों को देखते हुए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र योजना के तहत गृह मंत्रालय द्वारा संयुक्त साइबर अपराध समन्वय दल (जेसीसीटी) का गठन किया गया है। इससे अब दिल्ली व केंद्र शासित प्रदेश समेत कई राज्यों की पुलिस को साइबर अपराध से संबंधित डाटा साझा करने, काम करने के तरीके, वित्तीय साइबर जालसाजों के विवरण में समन्वय और सहयोग में मदद मिलेगा। द्वारका में एक कांफ्रेंस का आयोजन किया गया जहां विभिन्न राज्यों की टीमों ने अनुभव साझा किए।

डीसीपी साइबर सेल प्रशांत पी गौतम के मुताबिक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर शिकायतों के विश्लेषण के आधार पर मेवात क्षेत्र के लिए एक संयुक्त साइबर अपराध समन्वय टीम का भी गठन किया गया है। इसमें राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान की पुलिस को शामिल किया गया है। दिल्ली पुलिस को जेसीसीटी की नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। बुधवार को नोडल एजेंसी बनाई गई दिल्ली पुलिस की आइएफएसओ यूनिट



द्वारका स्थित साइबर सेल मुख्यालय में सम्मेलन के पश्चात पुलिस आयुक्त को पौधा भेंट करते विशेष आयुक्त स्पेशल सेल एचजीएस धालीवाल ● सौजन्य : दिल्ली पुलिस

द्वारका के कान्फ्रेंस हाल में संयुक्त साइबर अपराध समन्वय टीमों का एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा, विशेष आयुक्त स्पेशल सेल एचजीएस धालीवाल व इंडियन साइबर क्राइम को-आर्डिनेशन सेंटर के सीईओ राजेश कुमार समेत पुलिस के कई आला अधिकारी मौजूद थे। सम्मेलन में कई राज्यों के विभिन्न रैंक के 51 वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। तेलंगाना, हरियाणा, यूपी, गुजरात और झारखंड की पांच जेसीसीटी टीमों के प्रतिनिधियों ने साइबर अपराध में नवीनतम रुझानों, साइबर अपराध से निपटने की सीमाओं और हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय पर पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दीं। भाग लेने वाले राज्यों द्वारा जांच के दौरान देखे गए तौर-तरीकों को भी साझा किया गया ताकि सर्वोत्तम प्रथाओं को अन्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दोहराया जा सके। इस मौके पर हाट स्पाट के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। राज्यों द्वारा साझा किए गए इनपुट को संकलित कर लिया गया है। उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। संजय अरोड़ा ने प्रतिभागियों द्वारा इनपुट साझा करने की सराहना की।